



पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसी प्राचीन ममीज की खोज की है जिनके साथ मृतक के आदमकद कलर पोर्ट्रेट भी दफनाए गए थे। ये ममीज मिस्र के प्राचीन शहर फिलडैल्फिया के एक मकबरे में मिली हैं। कायरो के दक्षिण पश्चिम में 75 मील दूर फिलडैल्फिया शहर की स्थापना टोलमी काल (304 ईसापूर्व से 30 ईसापूर्व) में की गई थी, तब मिस्र पर सिकंदर महान के एक विख्यात सेनापति के वंशज राज कर रहे थे। प्राचीन फिलडैल्फिया कब्रिस्तान के उत्खनन मिशन के डायरेक्टर बासेन गेहाद ने कहा, उत्खनन के दौरान पुरातत्वविदों को ममी के पूरे बने दो पोर्ट्रेट और साथ ही कुछ आधे बने पोर्ट्रेट भी मिले। फिलडैल्फिया में दफनाए गए लोगों का सम्बंध अवश्य ही उच्च मध्यम वर्ग या अभिजात्य वर्ग से रहा होगा, इसलिए उनकी कब्रों में महंगे पोर्ट्रेट रखे गए थे। ये पोर्ट्रेट संभवतया भूमध्य सागर के तटवर्ती शहर एलैक्जैंड्रिया के कलाकारों ने बनाए थे। इस नई खोज से पहले, 1880 के दशक में हुए उत्खनन में भी ममी पोर्ट्रेट मिले थे। लुटेरों ने उन्नीसवीं सदी में फिलडैल्फिया सहित कई प्राचीन कब्रों को पोर्ट्रेट के लिए लूटा था। इसलिए पुरातत्व विशेषज्ञों को ज्यादा पोर्ट्रेट तो नहीं मिले पर विश्लेषण के लिए फिलडैल्फिया की कब्रों से कुछ पोर्ट्रेट अवश्य मिल गए। युनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के एथमोलीन म्यूजियम की प्रमुख क्यूरेटर, सूजन वॉकर ने बताया कि, रोमन ममी पोर्ट्रेट के लिए 1880 के दशक में कब्रें लूटी गई थीं। इनमें से अधिकांश पोर्ट्रेट वियना के डीलर और संग्रहकर्ता थियोडोर ग्राफ को बेच दी गई थीं। उसने इनका कैटलॉग बनाया और विश्वभर में इनकी प्रदर्शनी लगाई। अब कुछ पोर्ट्रेट म्यूजियमों में हैं तो कुछ अमीरों के निजी संग्रह में। वॉकर, जो खनन में शामिल नहीं थीं, ने कहा कि, नई खोज से ईजिप्शियन ममी पोर्ट्रेट पर और रौशनी पड़ सकेगी। क्योंकि इनकी आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से जांच की गई है। ममी पोर्ट्रेट के अलावा पुराविदों को कब्रिस्तान से एक इमारत के अवशेष और ईजिप्शियन यूनानी देवी आइसिस- एफ्रोडाइटी की मूर्ति मिली है, जिसे प्रेम की देवी कहा जाता है। एक पपायरी (भोज पत्र) के अवशेष भी मिले हैं, जिस पर मिस्र की कर्सिव स्क्रिप्ट और यूनानी भाषा में कुछ लिखा है।

विपक्ष चाहता है, अडानी प्रकरण किसी भी तरह जीवित रहे

भाजपा की रणनीति है, मीडिया व सोशल मीडिया के जरिये, “डैमेज कंट्रोल” हो

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने की कार्यवाही के अन्तर्गत, विपक्ष ने आज सरकार और अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञातव्य है कि अडानी ग्रुप तब विपक्ष के निशाने पर आया, जब अमेरिका की एक फर्म “हिन्दनबर्ग रिसर्च” ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में चालबाजी एवं फ्रॉड का आरोप लगाया था। तभी से विपक्ष यह माँग करता आ रहा है कि इस मुद्दे की जाँच या तो किसी संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाये या फिर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी जाँच-पड़ताल हो।

संसद भवन परिसर में लगी गांधी जी की मूर्ति पर किये गये विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद अपने हाथों तख्तियाँ लिये हुये थे, उन पर लिखे नारों में

‘संविदा पर लगे कर्मचारी को हटाकर दूसरा संविदाकर्मी नहीं लगा सकते’

जयपुर, 6 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि संविदा पर लगे कर्मचारी को हटाकर उसके साथ पर दूसरे संविदाकर्मी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रदूषण निव्यंत्रण

■ **राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहते हुये प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन व सचिव को नोटिस दिया तथा संविदा पर लगे आई.टी. अफसर को हटाने पर रोक लगा दी।**

मंडल के चेयरमैन व सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने मंडल में संविदा पर लगे आईटी ऑफिसर को पद से हटाने पर भी रोक लगा दी तथा उसे मौजूदा पद पर काम करते रहने को कहा है। जस्टिस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **दबाव बनाने के लिये विपक्ष की 16 पार्टियों ने संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने नारे बाजी व प्रदर्शन किया।**
- **विपक्ष के नारे थे, “मोदी -अडानी की पारी है, पैसे की लूट जारी है, “नहीं चलेगी और बेईमानी, बस करो मोदी -अडानी”, “एल.आई.सी. व एस.बी.आई. को बचाओ”।**
- **तृणमूल कांग्रेस ने, खड़गे के कक्ष में आयोजित विपक्ष के नेताओं की बैठक में भाग नहीं लिया। डैरेक ओ’ ब्रायन ने बाद में तर्क दिया कि, अब संसद की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालना चाहिये, क्योंकि, अब धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में सदस्यों को मौका मिलेगा, मोदी सरकार को “भेदने” का।**
- **पर बाद में तृणमूल कांग्रेस ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने विपक्ष द्वारा दिये गये धरने में भाग लिया।**

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और अरबपति (अडानी) के

बीच “यारी” के आरोप दिखाई दे रहे थे। उन्होंने “एल.आई.सी.” और “एस.बी.आई.” बचाओ के नारे भी लगाये। सांसदों ने गत सप्ताह स्थगन नोटिस पेश कर दिये थे तथा कहा था कि “जनता का पैसा बहुत बड़ी मात्रा में एस.बी.आई. तथा एल.आई.सी. के रास्ते अडानी ग्रुप की कैद में है।” किन्तु सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि बैंकों तथा बीमा कंपनियों की अरक्षितता (एक्सपोजर) अनुमत (परमिटेड) के अंदर ही है। कांग्रेस, द्रमुक, एन.सी.पी., बी.आर.एस., जद (यू), सपा, माकपा, भाकपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोक दल, आर.एस.पी., ए.ए.पी., आई.यू.एम.एल., राजद तथा शिवसेना (यू.बी.टी.) के सांसदों के हाथों में लगी तख्तियों पर “अडानी-मोदी में यारी है, पैसे की लूट जारी है”, “एल.आई.सी. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दू-मुस्लिम बहस शुरू करने के लिये एक बार फिर एक ऐतिहासिक प्रश्न उठाया है। उन्होंने एक पत्र का हवाला दिया है, जो काशी में एक मंदिर को ध्वस्त कर दिये जाने के बाद कथित रूप से शिवाजी

■ **आर.एस.एस. प्रमुख ने कहा कि, काशी का मंदिर तोड़ने पर छत्रपति शिवाजी महाराजा ने औरंगज़ेब को पत्र लिखकर कहा था कि, अगर यह सब बंद नहीं किया तो, वे अपनी तलवार उठाएंगे।**

महाराज ने बादशाह औरंगज़ेब को लिखा था। भागवत ने रविवार को एक समारोह में कहा, “एक मंदिर को ध्वस्त कर दिये जाने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब को एक पत्र लिखा था, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘शिवाजी ने लिखी थी औरंगज़ेब को चिट्ठी’

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कॉन्स्टेबल से हैडकॉन्स्टेबल पदोन्नति में विलम्ब का दोषी माना

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, राज्य सरकार ने गलत तथ्य पेश कर कई कॉन्स्टेबलों की पदोन्नति रोकी

जयपुर, 6 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में नागौर जिले में 2012-13 में कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल की पदोन्नति से जुड़े विवाद पर अदालत ने आदेश दिये हैं कि राज्य सरकार ने पदोन्नति के लिये रिक पदों की गणना गलत तरह से की है। अदालत ने अपने आदेश में आगे भी यह भी कहा कि कई कॉन्स्टेबल, जिन्हें वर्ष 2012-13 में ही हैड कॉन्स्टेबल के पद पर पदोन्नत कर देना चाहिये था, उन्हें सरकार ने गलत तथ्य देकर पदोन्नत नहीं होने दिया।

अदालत के इस फैसले से नागौर जिले में 28 और कॉन्स्टेबल्स की पदोन्नति का वर्ष 2013 माना जायेगा जबकि राज्य सरकार ने इन्हें 2014 या उसके बाद पदोन्नत किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता महावीर सिंह और अन्य की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद और एम.एम. महर्षि पैरवी के लिये पेश हुए। जैसा कि विदित है कि जयपुर जिले में भी कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल और हैड कॉन्स्टेबल से

- **इस फैसले के अनुसार पदोन्नति का वर्ष अब 2013 माना जाएगा।**
- **वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, इन गड़बड़ियों का असर प्रदेश में एस.आई. के दो से ढाई हजार पदों को भरने या उन पर पदोन्नति देने पर पड़ेगा।**

ए.एस.आई. के पदों पर पदोन्नति देने के मामले में राज्य सरकार ने गलती की थी, जिसे सरकार ने अदालत के समक्ष भी माना था। इस मामले में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने राज्य सरकार को आदेश दिये थे कि वह 377 ‘शैडो पोस्ट’ का गठन करें ताकि नियमानुसार योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति दी जा सके। वर्तमान मामले में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि उनके मुक्किलों को 2014 या उसके बाद पदोन्नति तो दे दी गई थी परंतु उन्होंने प्रमोशन कैडर कोर्स (पी.सी.सी.) 2013 में ही पास कर लिया था, जिसके बाद वे पदोन्नति के योग्य हो गये थे। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने उन्हें

पदोन्नति से नियम विरुद्ध रोक रखा था। उनसे कनिष्ठ कर्मियों को पदोन्नति दी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रणीत कौर ने “शो कॉज” नोटिस की खिल्ली उड़ाई

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। पार्टी के “शो कॉज” नोटिस के प्रति पूर्ण असम्मान दर्शाते हुए पटियाला की

■ **पंजाब की कांग्रेसी सांसद प्रणीत कौर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के प्रमुख तारिक अनवर पर निशाना साधा और कहा, “जिसने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और 20 साल से पार्टी से बाहर रहा और जो खुद अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर चुका है, वह मुझसे सवाल पूछ रहा है।”**

लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सी.डब्ल्यू.सी. के चुनाव होंगे?

24 से 26 फरवरी को आयोजित इस अधिवेशन में राहुल गांधी व प्रियंका चुनाव कराने के पक्ष में हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। इस बात को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है कि, 24 से 26 फरवरी रायपुर में होने वाले कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) के चुनाव होंगे या नहीं। यह पूछे जाने पर ए.आई.सी.सी. के संघटन प्रभारी ने कहा कि, इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निर्णय लेंगे।

सूत्रों ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इस बात पर भारी मतभेद हैं कि पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक समिति के लिए चुनाव होने चाहिए या नहीं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी चुनावों के पक्ष में हैं क्योंकि वे विविध प्रकार से पार्टी के अंदर चुनावों पर जोर देते रहे हैं। समझा जाता है कि अब प्रियंका गांधी भी चुनावों के पक्ष में हैं तो वे यह भी चाहेंगी कि वे सी.डब्ल्यू.सी. में मनोनीत होने के बजाय, स्वयं भी कार्य समिति में स्थान के लिये चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दे दी थी

■ **प्रियंका तो स्वयं चुनाव लड़कर सी.डब्ल्यू.सी. का सदस्य बनना चाहती हैं, केवल मनोनीत सदस्य नहीं रहना चाहतीं।**

■ **जैसा कि विदित ही है, कांग्रेस अध्यक्ष आधे सदस्य मनोनीत करते हैं तथा आधे चुनकर आते हैं।**

■ **राहुल गांधी स्वयं भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर अधिक संभावना है कि, कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे उन्हें सी.डब्ल्यू.सी. में मनोनीत करेंगे।**

■ **हाई कमान के अन्य वरिष्ठ नेता, सी.डब्ल्यू.सी. के सदस्यों का चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। वे इस बात से आशंकित हैं कि, खड़गे के खिलाफ कांग्रेसी अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर 1000 वोट पा गये थे, अधिकतर युवा नेताओं का।**

■ **ए.आई.सी.सी. के सदस्य सी.डब्ल्यू.सी. के सदस्यों को अपने मतों से चुनते हैं। पर अभी तक ए.आई.सी.सी. के सदस्यों की सूची जारी नहीं हुई है, हालांकि राज्यों ने अपनी सूचियाँ मुख्यालय भेज दी हैं।**

तथा 1000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिये थे क्योंकि उन्हें काफी युवा वोटरों का समर्थन मिल गया था, इस सब को

देखते हुये, शीर्ष नेता चुनाव कराये जाने की स्थिति में, काफी चौकन्ने रहने के लिये बाध्य हो जायेंगे।